PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 019
दि. 19.05.2026, मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत और नॉर्वे की ग्रीन रणनीतिक साझेदारी पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगी : पीएम मोदी

(जीएनएस)।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा से मुलाकात की और द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त संबोधन दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह देश नेचर और मानवीय विकास के बीच हार्मनी का एक सुंदर उदाहरण है।' उन्होंने आत्मीय स्वागत के लिए नॉर्वे सरकार और वहां की जनता का आभार भी व्यक्त किया।

संविधान दिवस और आतंकवाद के मुद्दे का किया जिक्र

पीएम मोदी ने नॉर्वे के संविधान दिवस के अवसर पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वह पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाले थे, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा, 'उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो इस एकजुटता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।'

भारत-यूरोप संबंधों के नए दौर का जिक्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया समेत कई क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय में भारत और यूरोप अपने संबंधों के नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार एसोसिएशन के बीच ऐतिहासिक व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता लागू किया गया। यह समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का ब्लूप्रिंट है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समझौते के तहत अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर निवेश और 10 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते को जमीनी परिणामों में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

ग्रीन रणनीतिक साझेदारी को मिला नया आयाम

नरेंद्र मोदी मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे अपने संबंधों को अब 'ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप' का स्वरूप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट रेजिलिएंस, ब्लू इकॉनमी और ग्रीन शिपिंग जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की तकनीक और पूंजी के

साथ जोड़कर दोनों देशों की कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी।

रिसर्च, एआई और स्पेस सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन दोनों देशों के संबंधों के मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि सस्टेनिबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर साझेदारी को फ्यूचर-रेडी बनाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी में भी सहयोग को और व्यापक किया जाएगा।

आर्कटिक और समुद्री सुरक्षा पर साझा फोकस

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नॉर्वे आर्कटिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश है और भारत के आर्कटिक रिसर्च स्टेशन 'हिमाद्रि' के संचालन में नॉर्वे का सहयोग अहम रहा है। उन्होंने कहा कि इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच हुआ एमओयू स्पेस सहयोग को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्वे की ग्रीन रणनीतिक साझेदारी पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नॉर्वे अब इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव से जुड़ रहा है और दोनों देश मरीन इकॉनमी, मैरीटाइम सिक्युरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग मजबूत करेंगे।

नॉर्वे पहुंचे पीएम मोदी, 43 वर्षों के बाद पहुंचा कोई भारतीय प्रधानमंत्री, यूरोप में नये युग की होगी शुरूआत

(जीएनएस)।

पीएम मोदी के दौरे को नॉर्वे के दूत मे-एलिन स्टेनर ने 'एतिहासिक' बताया है। मोदी का स्वागत करने हवाई अड्डे पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर पहुंचे थे जिनका पीएम मोदी ने आभार जताया है। 43 वर्षों के बाद किसी भारतीय पीएम का नॉर्वे दौरा हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत एयरपोर्ट पर नॉर्वे के पीएम ने किया।

ओस्लोः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिनों के दौरे पर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गये हैं। करीब 43 वर्षों के बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की धरती पर कदम रखा है। इससे पहले जून 1983 में इंदिरा गांधी ने नॉर्वे का दौरा किया था। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप एक गंभीर सुरक्षा संकट से जूझ रहा है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में मुश्किलें आ रही हैं और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के कारण हरित प्रौद्योगिकियों और आर्कटिक क्षेत्र में लोगों की दिलचस्पी

तेजी से बढ़ रही है। ओस्लो इस साल बहुप्रतीक्षित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिसमें मोदी और नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड के साथ साथ स्वीडन के नेता एक साथ शामिल हो रहे हैं।

पीएम मोदी ने नॉर्वे पहुंचने के बाद कहा "नॉर्वे के ओस्लो में मेरा आगमन हुआ। हवाई अड्डे पर मेरे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर का आभारी हूं। चार दशकों से भी अधिक समय में नॉर्वे की यह पहली प्रधानमंत्री-स्तरीय यात्रा है। मुझे विश्वास है कि यह भारत-नॉर्वे की मित्रता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। मैं महामहिम राजा हेराल्ड श और महारानी सोन्या से भेंट करूंगा और प्रधानमंत्री स्टोर के साथ वार्ता करूंगा। कल 19 तारीख को ओस्लो में तीसरा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा जो मेरे नॉर्डिक समकक्षों से मिलने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा।"

आपको बता दें कि दशकों तक भारत की महाद्वीपीय यूरोपीय रणनीतियां मुख्य रूप से पेरिस, बर्लिन और मॉस्को जैसे पारंपरिक दिग्गजों पर केंद्रित रहीं। लेकिन नई दिल्ली को धीरे-धीरे इस महाद्वीप के सुदूर उत्तरी क्षेत्र की ओर रुख करने का महत्व समझ में आने लगा। पांच नॉर्डिक देशों की संयुक्त ऋळ्ढ 1.9 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है और वे ग्रीन हाइड्रोजन, समुद्री नवाचार, डीप-टेक, सतत महासागर शासन और भू-तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक मानकों में अग्रणी हैं।

पीएम मोदी के दौरे को नॉर्वे के दूत मे-एलिन स्टेनर ने 'एतिहासिक' बताया है। उन्होंने फर्स्ट पोस्ट से बात करते हुए कहा "किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछली यात्रा 1983 में हुई थी इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा वास्तव में ऐतिहासिक है। हम 18 मई को नॉर्वे में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और कई सकारात्मक परिणामों तथा नॉर्वे-भारत संबंधों के और अधिक सुदृढ़ होने की आशा करते हैं।" आपको बता दें कि भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया 2018 में स्टॉकहोम में शुरू हुई और 2022 में कोपेनहेगन में जारी रही। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा अन्य देश है जो नॉर्डिक देशों के साथ इसी तरह का शिखर सम्मेलन करता है।

शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण मूल रूप से पिछले साल आयोजित करने की योजना थी लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। इस देरी के बावजूद इस संस्थागत ढांचे के पीछे की गति और भी बढ़ी है। शिखर सम्मेलन का यह प्रारूप एक अद्वितीय बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है जहां एक अत्यंत उन्नत क्षेत्रीय समूह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ सीधे तौर पर जुड़ता है।

संक्षिप्त समाचार

पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार' से नवाजे गए

गुटेनबर्ग।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विडिश सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए हैं। यह उनका 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। स्वीडन ने पीएम मोदी को अपने अत्यंत प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार' से सम्मानित किया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम मोदी को यह सम्मान सौंपा। इस सम्मान के साथ-साथ पीएम को एक बेहद खास और ऐतिहासिक उपहार एक बॉक्स भी दिया गया, जिसमें भारत के महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के दो हस्तलिखित कार्ड्स की हूबहू प्रतियां थीं, जो भारत-स्वीडन के पुराने सांस्कृतिक संबंधों को दशार्ती हैं।

'वह सेंचुरी पूरी कर लेंगे लेकिन...' पीमोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, संजय राउत ने कसा तंज

शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि इसका क्या करेंगे. हमको मना कर के खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं.

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को स्वीडन के प्रतिष्ठित सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' से सम्मानित किया गया. यह स्वीडन द्वारा किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है.'रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार' प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है. अब इस पर देश में सियासत शुरू हो गई है. शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तंज कसा है.

महाराष्ट्र में एक प्रेस वार्ता के दौरान राउत ने इस संदर्भ में सवाल पूछे जाने पर कहा- 'वह अवॉर्ड पाने के

मामले में अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे. वह जिस भी देश में जाते हैं, वहां का सबसे बड़ा अवॉर्ड उन्हें ही मिलता है. इस अवॉर्ड का करेंगे क्या? वह हमसे कहते हैं कि विदेश यात्राओं पर मत जाओ, और खुद अलग-अलग देशों का दौरा कर रहे हैं.'

इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'कुछ ही देर पहले मुझे 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस' से सम्मानित किया गया. यह न केवल मेरा, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का भी सम्मान है. यह स्वीडन में हमारे उन सभी मित्रों का भी सम्मान है, जिन्होंने भारत-स्वीडन संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान दिया और उन्हें एक मजबूत आधार प्रदान किया.'उन्होंने कहा, 'हमारे देशों के बीच मित्रता इसी तरह बढ़ती रहे.'

गोथेनबर्ग में आयोजित एक विशेष समारोह में स्वीडन की क्राउन प्रिंसेज विक्टोरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस' से सम्मानित किया, जो स्वीडन के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक है।

फिट इंडिया का नया जोशः दिल्ली में साइकिलिंग से कैसे बदल रही है लोगों की सेहत?

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया 'संडेज ऑन साइकिल' अभियान का 74वां संस्करण बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। जीएसटी

और सीमा शुल्क विभाग के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में नागरिकों, साइकिल चालकों और फिटनेस के प्रति जागरूक लोगों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त भारत के संदेश को बढ़ावा देना था। टैक्सपेयर सर्विसेज के एडिशनल डायरेक्टर (IRS) और फिट इंडिया एंबेसडर, श्री नरेंद्र कुमार यादव इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शारीरिक और मानसिक सेहत को दुरुस्त रखने के लिए साइकिल चलाने को सबसे प्रभावी और किफायती तरीका बताया। श्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि रोजाना साइकिल चलाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है।

योगी सरकार का फैसला, डॉ. लोहिया मेडिकल संस्थान में बनेगा 1010 बेड का अत्याधुनिक इमरजेंसी सेंटर

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को सम्पन्न कैबिनेट बैठक में लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 855 करोड़ 4 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि शहीद पथ पर गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 में डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नवीन परिसर, में 1010 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, नवीन ओपीडी ब्लॉक एवं टीचिंग ब्लॉक के निर्माण संबंधी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधाओं से

युक्त मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 1010 बेड स्थापित किए जाएंगे।

खन्ना ने बताया कि इसके साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या और बेहतर उपचार व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक नया ओपीडी ब्लॉक भी बनाया जाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को अधिक सुव्यवस्थित और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

परियोजना के अंतर्गत 200 सीटों की क्षमता वाला नया टीचिंग ब्लॉक भी विकसित किया जाएगा। इससे चिकित्सा छात्रों को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से युक्त शिक्षण वातावरण मिलेगा तथा मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार होगा।

इस नई चिकित्सा अवसंरचना के विकसित होने से गंभीर रोगियों को त्वरित और विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले मरीजों को भी राजधानी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, प्यार से माने तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगेः सीएम योगी आदित्यनाथ

यूपी के मुख यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वह अपने शासन में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत् तर प्रदेश के मुख् यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोग घर में नमाज करें या शिफ्ट में पढ़ें। सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।

लखनऊ में सोमवार को एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित् यनाथ शामिल होने आए थे। यहां उन् होंने कहा- 'लोग मुझसे पूछते हैं कि क् या आपके यूपी में लोग सड़कों पर सचमुच नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं पढ़ते। आपको विश्वास ना हो जाकर देख लो। सड़कें लोगों के चलने के लिए होती हैं। क्या अधिकार है किसी को आवागमन बाधित करने का। जहां

उसका स्थल होगा वहां जाकर करें। उन लोगों ने मुझसे कहा कि साहब कैसे होगा। हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा कि शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो जनसंख्या नियंत्रित कर लो।'

सरकार का नियम सबके लिए समान रूप से लागू होता है। सड़क पर अराजकता नहीं फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे तो ठीक है नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।

'संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में पढ़ें नमाज'

मुख्यमंत्री ने कहा- 'अगर सामर्थ्य नहीं है तो क्यों बेवजह संख्या बढ़ाए जा रहे हो। सिस्टम के साथ अगर रहना है तो नियम और कानून को मानना होगा। यहां कानून का राज होगा। अगर पढ़ना आवश्यक है तो आप शिफ्ट में पढ़िए। हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए है। एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं होने देंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप अगर संवाद से मानेंगे तो ठीक है नहीं तो संघर्ष करके भी देख लो। बरेली में इन लोगों ने ताकत आजमाया। देख लिया इनकी ताकत।'

पीएम मोदी ने केरलम के नए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन को दी बधाई, केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का दिया भरोसा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वी.डी. सतीशन को केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने नवगठित राज्य सरकार को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद और पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया

दिग्विजय सिंह की कमेटी ने एनटीए चीफ को किया तलब, क्या बदल जाएगा मेडिकल परीक्षा का सिस्टम?

(जीएनएस)।

देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को लेकर मचे विवाद के बीच अब मामला संसद की स्थायी समिति तक पहुंच गया है। परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली और सुधारों की समीक्षा करने का फैसला लिया है।

इस मुद्दे पर 21 मई को अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय और NTA के बड़े अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। इस बैठक में सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, बल्कि NTA में सुधार, अक का शिक्षा पर असर, रोजगार के अवसर, शिक्षक प्रशिक्षण और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ठएएळ परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा की घोषणा के बाद यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।

21 मई को होगी बड़ी बैठक

राज्यसभा की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, संसद की स्थायी समिति 21 मई को शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। बैठक में NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच और NTA सुधारों पर चर्चा होगी।

NTA चेयरपर्सन और शिक्षा सचिव तलब

समिति ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी और NTA चेयरपर्सन प्रदीप कुमार जोशी को बैठक में बुलाया है। उनसे परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के उपायों पर सवाल किए जाएंगे। समिति के राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट के लागू होने की स्थिति की भी समीक्षा करेगी।

करीब 23 लाख छात्रों ने दी थी NEET UG की परीक्षा

NEET-UG परीक्षा 3 मई को देशभर में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के लिए करीब 23 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

बक्से में लगा था ताला, पास में रखा था कपड़े का बड़ा बैग, खोलते ही अंदर से निकली महिला की सिर कटी लाश

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ट्रेन के अंदर एक बक्से में महिला का सिर कटा हुआ धड़ मिला तो पास रखे बैग में कटे हुए हाथ पैर मिले. इस घटना के बाद हर तरफ अफरा-तफरी मच गई.

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देना वाला मामला सामने आया है. जहां ट्रेन में महिला की सिरकटी लाश मिली है. छपरा से गोमती नगर के बीच 20 स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जीआरपी पुलिस जुटी है. छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस 20 स्टेशनों से गुजरते हुए 12 घंटे का सफर पूरा करती है. कल इसी ट्रेन में 25 से 30 वर्षीय महिला की सिर कटी लाश मिली थी. यह लाश गोमती नगर के आखिरी स्टेशन में स्लीपर कोच एसी 1 में लाश मिली थी.

बताते चले कि जीआरपी ट्रेन के अंदर रूटीन चेकिंग कर रही थी, इस दौरान कोच में एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला. बॉक्स में महिला की सिर कटी लाश का धड़ मिला और बैग में कटे हुए हाथ ,पैर मिले. इलेक्ट्रॉनिक कटर या बेहद धारदार हथियार से शव काटे जाने का शक जताया जा रहा है. शव के पांच टुकड़े मिले और वहीं सिर गायब मिला. हैरान कर देने वाली बात यह है कि शव पर कोई भी चोट का निशान नहीं मिला है. कहीं खून के धब्बे भी नहीं मिले. शव की शिनाख्त में जीआरपी पुलिस जुटी हुई है. वारदात के खुलासे के लिए एसपी जीआरपी ने तीन टीम बनाई है. चारबाग रेलवे स्टेशन के थाना जीआरपी में एफआईआर दर्ज हुई है.

इस पूरे मामले को लेकर एसीपी रेलवे रोहित मिश्र ने का बयान भी सामने आय है. उन्होंने केस की जानकारी देते हुए कि मामला दर्ज कर लिया गया है और तीन टीमों को हत्याकांड के खुलासे की जिम्मेदारी भी सौंपी जा चुकी है. फिलहाल अब तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बोगी में आरक्षित टिकट वाले यात्रियों का ब्योरा लिया गया है. हालांकि, सामान्य टिकट वाले भी उसमें सवार थे. इससे जांच में दिक्कत हो सकती है.

परीक्षा देने आ रहे छात्र की ट्रेन से गिरकर मौत, गंगागंज में एयरटेल फैक्ट्री के पास हुई घटना

(जीएनएस)।

लखनऊ। जौनपुर से दुबग्गा के एक स्कूल में चाचा के साथ सीयूईटी की परीक्षा देने आ रहा रहे युवक की गंगागंज में एयरटेल फैक्ट्री के पास ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। उसके चाचा चारबाग स्टेशन पहुंचे और खोजबीन की तो युवक ट्रेन पर नहीं मिला। उन्होंने भतीजे के नंबर पर संपर्क किया तो गोसाईगंज पुलिस ने युवक के ट्रेन से गिरकर मौत होने की बात कही।

पुलिस के मुताबिक, जौनपुर स्थित न्यू कालोनी नई गंज के रहने वाले 20 वर्षीय अंश खरवार ने इसी वर्ष बारहवीं की परीक्षा पास की थी। चाचा अजय खरवार ने बताया कि मंगलवार को भतीजे की दुबग्गा के एक स्कूल

में सीयूईटी की परीक्षा थी। सोमवार को वह परीक्षा दिलवाने के लिए भतीजे के साथ ट्रेन से लखनऊ आ रहे थे। दोनों लोग अपनी सीट पर बैठे थे।

सुबह सात बजे भतीजे ने उनसे पानी पीने जाने की बात कही और जाकर बोगी के गेट पर खड़ा हो गया। संदिग्ध परिस्थितियों में वह गंगागंज स्थित एयरटेल फैक्ट्री के पास ट्रेन से नीचे गिर गया। चारबाग पहुंचने पर भतीजा नहीं मिला।

उन्होंने यात्रियों से पूछा तो पता चला कि कुछ दूर पहले एक युवक झपकी आने से ट्रेन से नीचे गिरा था। उन्होंने अंश के नंबर पर फोन किया तो गोसाईगंज पुलिस ने बताया कि वह अचेत अवस्था में ट्रेन की पटरी किनारे चोटिल पड़ा मिला था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने पर मौत की पुष्टि हुई। गोसाईगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है।

लखनऊ में बैंक का क्रेडिट कार्ड मैनेजर बताकर युवक से की ठगी, मुकदमा दर्ज

(जीएनएस)।

लखनऊ। विकासनगर निवासी एक युवक से खुद को बैंक का क्रेडिट कार्ड मैनेजर बताकर 1.80 लाख रुपये की ठगी हुई है। विकासनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

विकासनगर निवासी आशुतोष सिंह के मुताबिक पांच दिसंबर 2025 को शुभम श्रीवास्तव नामक युवक ने फोन कर खुद को कोटक महिंद्रा बैंक की लेखराज शाखा का क्रेडिट कार्ड मैनेजर बताया। आरोपित ने कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड पर करीब 1.80 लाख रुपये की बकाया राशि है और भुगतान न करने पर कार्ड ब्लाक कर दिया जाएगा, जिससे सिबिल रेटिंग खराब हो जाएगी।

आरोप है कि आरोपित ने डर और भ्रम पैदा कर यह भरोसा दिलाया कि यदि भुगतान उसकी 'स्टाफ आइडी' के माध्यम से किया गया तो बैंक की योजना के तहत रिफंड और बोनस प्वाइंट्स मिलेंगे। विश्वास दिलाने के लिए आरोपित ने वाट्सएप पर बैंक कर्मचारी का कथित पहचान पत्र भी भेजा, जो बाद में फर्जी निकला।

पूछताछ करने पर आरोपित बैंक सर्वर में खराबी का बहाना बनाता रहा। बाद में आरोपित ने 1.50 लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन बैंक में लगाने पर पता चला कि उस पर पहले से ही 'स्टाप पेमेंट' लगा था। ऑनलाइन भुगतान की फर्जी रसीद देकर गुमराह किया। आरोपित के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कई लोगों से ठगी कर चुका है। मामले में महीप शुक्ला आरोपित का मददगार निकला।

अमेरिका ने इमरान को किया सत्ता से बेदखल! सामने आए कागज - मचा हंगामा, क्या थी वजह?

(जीएनएस)।

अमेरिका के पत्रकारों द्वारा बनाई गई वेबसाइट उ‹ङ्कस्र‹ ‹र्३ी ठी६२ ने एक नई रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ था। दावा किया गया कि अमेरिका ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि वह पाकिस्तान में अपनी जी-हुजूरी करने वाली सरकार बिठाए और पाकिस्तान को अपने मन मुताबिक चला सके। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इसके बाद आने वाले सालों में पाकिस्तान ने लगभग हर उस अमेरिकी मांग को मान लिया, जिसे इमरान खान ने पहले ठुकराते रहे।

कहां से लीक हुई रिपोर्ट?

Drop Site की इस जांच में कहा गया है कि यह पूरी स्टोरी लीक हुए राजनयिक केबल, सरकारी दस्तावेज और अंदरूनी सूत्रों के इंटरव्यू पर आधारित है। रिपोर्ट ने पहली बार केबल I-0678 को भी सार्वजनिक किया है, जिसे उसने वह दस्तावेज बताया है जिसने इमरान खान को सत्ता से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

अमेरिका-पाकिस्तान रिश्तों में तनाव की कहानी

रिपोर्ट के मुताबिक, कई सालों से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा था। 2021 में एक अमेरिकी अधिकारी ने वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत से कथित तौर पर कहा था कि अगर इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जाता है, तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। हालांकि अमेरिकी सरकार ने हमेशा किसी भी तरह की दखलअंदाजी से इनकार किया है।

इमरान ने CIA प्रमुख बिठाए रखा, नहीं की मीटिंग

रिपोर्ट में बताया गया कि जून 2021 में WilliÔm J. Bur»»fs, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी उक्अ के

प्रमुख हैं, इस्लामाबाद पहुंचे थे। उनका मकसद अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी से पहले पाकिस्तान का सहयोग लेना था, जिसमें ड्रोन ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल भी शामिल था। लेकिन इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। कहा गया कि उन्होंने साफ कर दिया था कि वह केवल अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Bide»»f से ही बात करेंगे। बाइडेन ने भी कई बार इमरान खान के कॉल रिक्वेस्ट को अनदेखा किया था। इसके बाद बर्न्स को पूरे दिन इंतजार करना पड़ा, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई।

अफगानिस्तान संकट और बढ़ता तनाव

कुछ हफ्तों बाद अफगानिस्तान में हालात बिगड़े और काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। इस घटना ने बाइडेन प्रशासन की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद इमरान खान ने अमेरिकी मांगों को और भी ज्यादा सख्ती से खारिज करना शुरू कर दिया, जिसमें पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य बेस बनाने का प्रस्ताव भी शामिल था।

इमरान की रूस यात्रा और अमेरिका की नाराजगी

फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। उसी दिन इमरान खान मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे थे। रिपोर्ट की मानें तो अमेरिका ने उन्हें यह यात्रा रद्द करने को कहा था, लेकिन इमरान खान ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिस पर बाइडन आगबबूला हो गए।

9 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से हटा दिया गया। उ‹ङ्कस्र‹ ‹र्३ी की रिपोर्ट का दावा है कि यह केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरे रणनीतिक और कूटनीतिक कारण भी थे। इसके बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पर भी सख्त कार्रवाई शुरू हुई जैसे- चुनाव चिन्ह छीनना, नेताओं को अरेस्ट करना या पार्टी छुड़वाने पर मजबूर करना। खुद इमरान खान भी कुछ दिन बाद गिरफ्तार हो गए।

पाकिस्तान की विदेश नीति में बड़ा बदलाव

रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान के हटने के बाद पाकिस्तान की विदेश नीति तेजी से बदल गई।अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग फिर से शुरू हुआ, खाड़ी देशों के साथ रिश्ते बेहतर हुए और चीन से दूरी बढ़ने लगी। चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर (CPEC) की के कई प्रोजेक्ट अलग-अलग कारणों से रोक दिए गए। यहां तक कि सेना भी अमेरिका के इशारे पर अपने फैसले लेने लगी।

नई सरकार को मिलने लगा पैसा

जुलाई 2023 में क्ट्रह्नने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर का बेलआउट दिया। इसके बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कुछ हद तक स्थिर हुई और पश्चिमी देशों की आलोचना भी कम हो गई। इसके अलावा पूर्व सेना चीफ कमर जावेद बाजवा ने वॉशिंगटन जाकर अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की जिसमें उन्हें मिसाइल प्रोग्राम रोकने और चीन से दूर रहने की हिदायत मिली।

बाइडेन के इशारे पर बाजवा गए और मुनीर आए?

इसके बाद राष्ट्रपति खड्ढी ड्डीाॅल्ल ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया। इसके तुरंत बाद बाजवा ने रिटायरमेंट ले लिया और उनकी जगह आसिम मुनीर को गद्दी सौंपी गई। इससे पहले मुनीर को इमरान ने क्रक चीफ के पद से हटा दिया था।

सऊदी अरब समझौता और नए रिश्ते

2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस समझौता किया। यह वही समझौता था जिसे इमरान खान ने पहले समर्थन नहीं दिया था।वइसके बाद पाकिस्तान और अमेरिकी कंपनियों के बीच 500 मिलियन डॉलर का दुर्लभ खनिज समझौता हुआ।

खुद को पीएम मोदी का करीबी बताकर ठगी करने के आरोपी मोहम्मद काशिफ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

(जीएनएस)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी सहयोगी बताकर लोगों से कथित ठगी करने के आरोपी मोहम्मद काशिफ को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने लंबे समय से जेल में बंद रहने को ध्यान में रखते हुए यह राहत प्रदान की।

मोहम्मद काशिफ को अप्रैल 2023 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपनी मॉर्फ्ड तस्वीरें अपलोड कर खुद को शीर्ष सरकारी अधिकारियों का करीबी बताया।

इस मामले में उसके खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं और क्ळ Act की धारा 66ऊ के तहत FIR दर्ज हुई थी। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसी FIR के आधार पर एउक्क्ष दर्ज कर PMLA के तहत उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2024 में उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाल ही में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने दोबारा उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना लंबी हिरासत को देखते हुए आरोपी को जमानत दे दी।

उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूएपीए केस में बेल खारिज होने पर कोर्ट ने पूछा सवाल-ट्रायल नहीं, फिर जेल क्यों?

(जीएनएस)।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी वअढअ के तहत लंबी अवधि तक जेल में बंद आरोपियों को जमानत देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 18 मई को अहम टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत की एक पीठ ने उमर खालिद और शरजील इमाम से जुड़े पहले के एक फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि बेल नियम है और जेल अपवाद, यहां तक कि वअढअ जैसे सख्त कानूनों के मामलों में भी।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर के एक आरोपी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए की। अंद्राबी पिछले पांच साल से कथित नार्को-टेररिज्म मामले में जेल में बंद थे।

उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जनवरी 2026 में जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले पर भी अप्रत्यक्ष रूप से असहमति जताई। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद और शरजील इमाम 2020 के दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश का हिस्सा थे। दोनों पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद हैं। हालांकि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले गलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी थी। अब नई पीठ ने उस फैसले को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा-'जेल नहीं, बेल नियम है'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था में मूल सिद्धांत यह है कि बेल नियम है और जेल अपवाद। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत वअढअ जैसे कानूनों में भी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत मिले मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं और किसी भी सख्त कानून की व्याख्या करते समय अदालतों को इन्हें ध्यान में रखना होगा। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि UAPA के तहत जमानत मिलना बेहद मुश्किल माना जाता है।

लाइव लॉ और बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की पीठ ने कहा कि अदालत 2021 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब फैसलै का सही तरीके से पालन नहीं किया। के.ए. नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने कहा था कि अगर किसी आरोपी का ट्रायल लंबे समय तक शुरू नहीं होता या पूरा नहीं हो पाता, तो केवल इस आधार पर भी जमानत दी जा सकती है, भले ही मामला वअढअ जैसे सख्त कानून के तहत हो। पीठ ने कहा कि लंबे समय तक बिना ट्रायल के जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।

पांच साल से जेल में थे सैयद इफ्तिखार अंद्राबी

जिस मामले में यह टिप्पणी की गई, उसमें जम्मू-कश्मीर के सैयद इफ्तिखार अंद्राबी पर कथित नार्को-टेररिज्म गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। वे 2020 से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रायल में अत्यधिक देरी हुई है और आरोपी को इतने लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है। इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

क्या है UAPA और जमानत का कानूनी गणितः क्यों अहम हैं सुप्रीम कोर्ट के ये दो फैसले?

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई के दौरान यूएपीए (वअढअ) मामलों में जमानत को लेकर दो अहम फैसलों - यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) और गुरविंदर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2024) के बीच कानूनी अंतर और विरोधाभास को दिखाता है। अदालत ने साफ संकेत दिया कि लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने की स्थिति में किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

1. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021): लंबी हिरासत जमानत का आधार

साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने वल्लङ्कल्ल ङ्का क्ल्लर्‍ ५२ ङअ द्धीु मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। अदालत ने कहा था कि अगर किसी आरोपी का ट्रायल लंबे समय तक पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यूएपीए की धारा 43उ(5) जैसी सख्त शर्तों के बावजूद उसे जमानत दी जा सकती है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 21 को प्राथमिकता दी थी। अदालत का मानना था कि किसी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर वर्षों तक जेल में रखना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है।हालिया सुनवाई में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मुकदमे में देरी और लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का वैध आधार माना जाना चाहिए।

2. गुरविंदर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2024): वअढअ में जमानत को और सख्त बनाया गया

इसके विपरीत, साल 2024 में आए ऋ४१६ल्लीी१ ?ल्लँ ५२ वल्लङ्कल्ल ङ्का क्ल्लर्‍ फैसले में वअढअ के तहत जमानत के नियमों को काफी कठोर तरीके से लागू किया गया था। इस फैसले में अदालत ने के.ए. नजीब मामले के सिद्धांतों को सीमित दायरे में देखा और यह संकेत दिया कि केवल लंबी हिरासत अपने आप में जमानत का पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस पर असहमति जताई। अदालत ने कहा कि गुरविंदर सिंह फैसले में नजीब केस की मूल भावना और संवैधानिक सिद्धांतों का पर्याप्त सम्मान नहीं किया गया। पीठ ने स्पष्ट किया कि यूएपीए जैसे सख्त कानून भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकते और अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष न्याय के अधिकार को संतुलित तरीके से देखना होगा।

क्या उमर खालिद और शरजील इमाम को मिल सकती है राहत?

सुप्रीम कोर्ट की नई टिप्पणियों के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे मामलों में भी आगे राहत की संभावना बन सकती है। हालांकि अदालत ने सीधे तौर पर उनके मामलों में कोई नया आदेश नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से पहले के फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं, उससे भविष्य में कानूनी रणनीति और बहस प्रभावित हो सकती है। फिलहाल इस मामले ने एक बार फिर वअढअ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लंबी न्यायिक हिरासत को लेकर देश में बड़ी बहस छेड़ दी है।

शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा प्रदर्शन, छाती के बल रेंगते हुए पहुंचे मंत्री के घर

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर सोमवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया. जिसमें अभ्यर्थियों ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर जमकर नारे लगाए. अभ्यर्थी भीषण गर्मी और तपती सड़क पर छाती के बल रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे. अभ्यर्थियों ने कहा कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. यह 31वीं तारीख है. लेकिन कहीं कोई पैरवी नहीं हो रही है. कम से कम सही तरीके से पैरवी करके उनके मुद्दे को उठाया जाए.

प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का कहना है कि 69000 शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की बजाए महज 3.68% और एससी को 21% की जगह केवल 16.2% आरक्षण मिला है. दूसरी ओर बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि यह मामला कोर्ट में लंबित है.

क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती निकली थी. आरोप है कि उसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार आरक्षण नहीं मिला. यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले की सुनवाई कल 19 मई को होनी है. सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमजी मसीह की पीठ कर रही है. शीर्ष अदालत ने फिलहाल इलाहाबाइ हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा रखी है. हाईकोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट रद्द करके तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चार फरवरी को सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों के संबंध में सरकार क्या सोच रही है. अदालत ने प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था.

2018 से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी

यह पहला मौका नहीं है, जब अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है. वे साल 2018 से ही सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं. प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने सही से हमारी पैरवी करनी चाहिए.

भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने को देश के लिए गौरव बताया

(जीएनएस)।

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष सम्मान, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया जाना प्रत्‍येक देशवासी के लिए अत्यंत गर्व की बात है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त होने वाला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत उपलब्धि की पहचान नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतीयों की क्षमता और

उत्कृष्टता को स्थापित करने का प्रतीक है।

श्री त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात-यू.ए.ई. ने एक समझौता किया। इसके अंतर्गत वह भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को 30 अरब बैरल तक बढ़ाएगा। इसके अलावा, यू.ए.ई. की एक कंपनी ने भारत में पांच अरब डॉलर के निवेश की घोषणा भी की है। श्री मोदी के प्रयासों के कारण चोल काल की तांबे की प्लेटें नीदरलैंड्स से भारत को वापस मिल रही हैं।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

रणनीतिक अथवा व्यापारिक परियोजनाओं का पूरा होना अपरिहार्य

देश के राजनेता और राजनीतिक पार्टियों को जब अपने से ज्यादा दूसरे के हितों की किसी भी कारणवश चिन्ता सताए तो उस देश का बंटाधार होना निश्चित है। भारत सरकार अपने बड़े सुरक्षा रणनीतिक उद्देश्य के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप, मलक्का जलडमरूमध्य के एकदम निकट स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त मागरे में से एक है। इस क्षेत्र में मजबूत मौजूदगी होने से भारत वैश्विक समुद्री मार्गो और हिन्द महासागर में चीनी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। चीन की चिन्ता को अपनी चिन्ता मानने वाले भारतीय नेताओं का सक्रिय होना स्वाभाविक है। इसीलिए जब रविवार को कांग्रेस के एक बड़े नेता और चीन के भारत में प्रचण्ड समर्थक जयराम रमेश ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर दोबारा अनुरोध किया कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाए क्योंकि इससे न सिर्प पर्यावरण को नुकसान होगा बल्कि स्थानीय आदिवासी समुदाय की भावनाओं की उपेक्षा भी होगी।

दरअसल जयराम रमेश ने इस मेगा प्रोजेक्ट के खिलाफ पहले भी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर पाटी की तरफ से अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं। इसके बाद पाटी के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने भी उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां भारत सरकार ने 92000 करोड़ रुपए से इस अति महत्वाकांक्षी परियोजना का श्री गणेश करने जा रही है। सवाल यूं ही नहीं पूछे जाते कि कांग्रेस और चीन के बीच यह वैसा रिश्ता है कि जब भी चीनी हितों को भारतीय नीति, रणनीति या निर्माण से चुनौती की संभावना होती है तो इस पाटी के नेताओं के पेट में ऐंठन शुरू हो जाती है।

यह सच है कि पर्यावरण देश की बहुत बड़ी चिन्ता है किन्तु जो रणनीतिक अथवा व्यापारिक परियोजनाएं अपरिहार्य हैं, उन्हें तो पूरा करना ही होगा। विकास और पर्यावरण में संतुलन बैठाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यदि समुद्री जीवों की इतनी ही चिन्ता की जाए तो बन्दरगाह निर्माण और विकास का कोई कार्य ही नहीं हो सकता। आज तो बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक की जरूरतों को देखकर सरकारें समुद्र तल पर रोड निर्माण की परियोजनाएं बनाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान जयराम रमेश खुद पर्यावरण मंत्री थे और सरकार नेवीगेशन के लिए रामसेतु तोड़ने के लिए सेतु समुद्रम परियोजना को मंजूरी दे दी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की आस्था की उपेक्षा के मुद्दे पर अनुमति देने से मना कर दिया था। अब तो इस परियोजना पर विचार होना ही असंभव है। सच तो यह है कि चीन अपने वुछ पालतू बुद्धिजीवियों और राजनेताओं को खरीदकर रखता है जो उसको जरूरत पड़ने पर परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं। चीन ने तो प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पाटी से एमओयू कर रखा है कि यह पाटी एक दूसरे के हितों के लिए काम करेंगे। संयोग देखिए चीन में ओलम्पिक के आयोजन के अवसर पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आमंत्रित था और जयराम रमेश भी वहीं पर मौजूद थे। जब कांग्रेस की तरफ से एमओयू पर हस्ताक्षर राहुल गांधी ने की तो उस वक्त यही जयराम रमेश ज्ञान बांट रहे थे कि उन्हें इस बात को जानकर हैरानी होती है कि आखिर भारत के वाणिज्य विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी चीनी व्यापारिक प्रस्तावों पर तत्काल मंजूरी देने में देर क्यों करते हैं! मजे की बात तो यह है कि जब वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री सार्वजनिक रूप से किसी देश की धरती पर अपने ही विभाग के अधिकारियों की आलोचना करेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा अफसरशाही पर! लब्बोलुआब यह है कि हित कोई भी हो, वह राष्ट्रहित से बड़ा कदापि नहीं हो सकता। चीन ने तो पाकिस्तान में ग्वादर, बांग्लादेश का चटगांव और श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसे बंदरगाह बनाकर भारत के खिलाफ घेराबन्दी कर चुके हैं और आज जब भारत 'ग्रेट निकोबार परियोजना' के माध्यम से चीन की परवाह किए बगैर अपने रणनीतिक महत्व को मान्यता देने का साहसिक एवं सराहनीय परियोजना शुरू करने जा रहा है तो चीन के समर्थन में भारत के ही वुछ राजनेता इस परियोजना की बेशमी से आलोचना कर रहे हैं। 1962-63 में यही काम भारतीय कम्यूनिस्ट पाटी ने भी किया था। जब भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के खिलाफ रक्षात्मक भूमिका निभा रहे थे तो भारत के कामरेड हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू और भारतीय सेना को हमलावर बता कर युद्ध के लिए दोनों को जिम्मेदार बता रहे थे। उस विचारधारा का तो सत्यानाश हो गया। आज वह विचार धारामात्र जेएनयू तक सिमट कर रह गई है पता नहीं, कांग्रेस के वुछ लोग उसी विचारधारा को गले में लपेट कर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पाटी को उच्छिन्न करने पर तुले हैं। ऐसे लोग देश में राष्ट्रीय हितों के खिलाफ तो काम करते ही हैं, अपनी पाटी की भी छवि खराब करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का दूरदर्शी आ'ान: पेट्रोलियम और स्वर्ण खपत से आर्थिक स्वराज की ओर

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोलियम और स्वर्ण की खपत को संयमित करने का आ'ान केवल एक आर्थिक सलाह नहीं है, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक वित्तीय स्थिरता से जुड़ा हुआ दूरदर्शी राष्ट्रीय चिंतन है।

पहली दृष्टि में यह विषय सामान्य प्रतीत हो सकता है, किंतु इसकी गहराई में उतरने पर स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक दबाव डालने वाले दो प्रमुख आयात कच्चा तेल और स्वर्ण ही हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री का यह संदेश मात्र बचत का आग्रह नहीं, बल्कि आर्थिक स्वराज की सिद्धि का राष्ट्रमंत्र है।

भारत आज विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित है। उद्योगों का विस्तार, बढ़ती जनसंख्या, परिवहन की आवश्यकता और ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग ने पेट्रोलियम पर हमारी निर्भरता को अत्यधिक बढ़ा दिया है। स्थिति यह है कि भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 80 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसका अर्थ यह है कि देश की ऊर्जा व्यवस्था का बहुत बड़ा भाग विदेशी बाजारों, वैश्विक संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों की अस्थिरता पर निर्भर है।

जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका सीधा प्रभाव भारतीय अर्थतंत्र पर पड़ता है। पेट्रोल-डीजल महंगे होते हैं, परिवहन लागत बढ़ती है, उद्योगों का व्यय बढ़ता है और अंततः महंगाई आम नागरिक तक पहुंचती है। एक प्रकार से तेल केवल ईंधन नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की धमनियों में बहने वाला रक्त है। यदि यह रक्त अत्यधिक महंगे आयात पर निर्भर रहेगा, तो आर्थिक शरीर पर दबाव स्वाभाविक है।

इसी प्रकार स्वर्ण के प्रति भारतीय समाज का भावनात्मक और सांस्कृतिक आकर्षण भी हमारी वित्तीय संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता है और अपनी आवश्यकता का लगभग पूरा सोना विदेशों से आयात करता है। विवाह, परंपराएं, निवेश और सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सभी कारणों से भारत में सोने की मांग लगातार बनी रहती है। लेकिन इसका आर्थिक पक्ष अत्यंत गंभीर है।

जब भारत भारी मात्रा में सोना खरीदता है, तो उसके बदले विदेशी मुद्रा विशेषकर अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। यही स्थिति तेल के साथ भी है। परिणामस्वरूप देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार निरंतर बाहर जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह होता है। यही भंडार संकट के समय आयात, अंतरराष्ट्रीय भुगतान और वित्तीय स्थिरता को संभालता है। यदि यह भंडार अत्यधिक दबाव में आए, तो रुपए की कीमत कमजोर होने लगती है, आयात महंगे हो जाते हैं और वैश्विक बाजार में देश की आर्थिक साख प्रभावित होती है।

यही कारण है कि प्रधानमंत्री का यह आ'ान सिर्फ 'कम खर्च' का संदेश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन का अभियान है। यदि भारत पेट्रोलियम की खपत और स्वर्ण के प्रति अंधाधुंध निवेश प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सके, तो आयात बिल में भारी कमी लाई जा सकती है। आयात बिल में होने वाली इस अरबों डॉलर की बचत का उपयोग देश के आंतरिक विकास, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सैन्य सशक्तिकरण, उन्नत शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं में किया जा सकेगा।

महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध का ही नहीं, बल्कि 'संयमित कर्म' का भी उपदेश दिया था। भारतीय चिंतन में संसाधनों का अनियंत्रित उपभोग कभी आदर्श नहीं माना गया। यही कारण है कि हमारी सभ्यता ने 'यज्ञ' की अवधारणा दी, जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि व्यापक लोककल्याण के लिए त्याग और अनुशासन अपनाता है। पेट्रोलियम, स्वर्ण और विदेशी मुद्रा संरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आ'ान भी उसी 'राष्ट्रयज्ञ' का आधुनिक स्वरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सजग भागीदारी आवश्यक है।

भारतीय समाज में सोने को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से तिजोरियों और लॉकरों में बंद यह सोना एक 'डेड इन्वेस्टमेंट' (निष्क्रिय निवेश) है, जो देश के आर्थिक चक्र में कोई योगदान नहीं देता। यहीं भारतीय निवेश प्रवृत्ति पर पुनर्विचार की आवश्यकता सामने आती है। यदि देश का नागरिक सोने के भौतिक उपभोग को कम करे या इसके विकल्प के रूप में सरकार के 'सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड' (रञ्ज) जैसे डिजिटल साधनों को अपनाए, तो वह पैसा देश के बैंकिंग सिस्टम और विकास कार्यों में लगा रहेगा। यह दृष्टि भारत को निष्क्रिय संचय से उत्पादक निवेश की दिशा में ले जाने का प्रयास है। 'देखो अपना देश' और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का आग्रह भी

इसी व्यापक आर्थिक दृष्टि का हिस्सा है। हर वर्ष करोड़ों भारतीय विदेश यात्राओं पर विशाल मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। यदि उसी खर्च का एक बड़ा भाग भारत के पर्यटन स्थलों काशी, अयोध्या, केदारनाथ, लक्षद्वीप, अंडमान, पूर्वोत्तर, राजस्थान, कच्छ, केरला या हिमालयी क्षेत्रों पर हो, तो उसका सीधा लाभ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

घरेलू पर्यटन महज यात्रा नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था का जीवन-तंत्र है। इससे होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार, रेस्तरां, गाइड, टैक्सी चालक और छोटे व्यापारी सभी सशक्त होते हैं। एक पर्यटक केवल पैसा खर्च नहीं करता, वह स्थानीय रोजगार को गति देता है। इस दृष्टि से यह आ'ान 'देश का पैसा देश में' रखने का आर्थिक मंत्र भी है।

भारत के इतिहास में ऐसे राष्ट्रीय आ'ानों की एक गौरवपूर्ण परंपरा रही है। जब-जब देश चुनौतियों से घिरा, तब-तब नेतृत्व ने केवल शासनादेश नहीं दिए, बल्कि जनचेतना को जगाने का प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री का वह ऐतिहासिक आ'ान आज भी स्मरणीय है, जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था और उन्होंने राष्ट्रहित में सप्ताह में एक दिन उपवास रखने का आग्रह किया था। वह केवल भोजन बचाने की अपील नहीं थी, वह आत्मसंयम, अनुशासन और राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत सुविधा का त्याग करने की भारतीय परंपरा का जागरण था। देशवासियों ने भी उसे आदेश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व के रूप में स्वीकार किया। घरों में चूल्हे कम जले, होटलों ने भोजन परोसना बंद किया और समाज ने यह सिद्ध किया कि भारत केवल सरकारों से नहीं, बल्कि जनभागीदारी से चलता है।

इसी प्रकार समय-समय पर देश के नेतृत्व ने स्वदेशी, बचत, आत्मनिर्भरता और उत्पादन बढ़ाने जैसे आ'ानों के माध्यम से जनता को राष्ट्रनिर्माण में सहभागी बनाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश उसी राष्ट्रीय परंपरा का आधुनिक विस्तार है। अंतर केवल परिस्थितियों का है, तब चुनौती खाद्यान्न की थी, आज चुनौती ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की है। किंतु दोनों के मूल में 'राष्ट्र प्रथम' का ही भाव है।

भारतीय राष्ट्रचिंतन में आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता की यह परंपरा केवल राजनीतिक नीतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे सभ्यतागत दृष्टि के रूप में देखा गया। महात्मा गांधी ने स्वराज को केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं देखा था। उनके चिंतन में स्वराज, ग्राम स्वराज और आर्थिक स्वराज एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। उनका मानना था कि जब गांव आत्मनिर्भर होंगे, स्थानीय उत्पादन सशक्त होगा, संसाधनों का संयमित उपयोग होगा और राष्ट्र आर्थिक रूप से बाहरी निर्भरता से मुक्त होगा, तभी वास्तविक स्वराज की स्थापना संभव होगी।

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत, 'वोकल फॉर लोकल', स्थानीय पर्यटन, ऊर्जा संरक्षण और स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से उसी आर्थिक स्वराज की आधुनिक अवधारणा को मूर्त रूप दे रहे हैं। वे केवल नीतियों के निमार्ता नहीं, बल्कि आधुनिक भारत में आर्थिक स्वराज के शिल्पकार हैं। वास्तव में पूर्ण स्वराज का रास्ता आर्थिक स्वराज और ग्राम स्वराज से होकर ही निकलता है।

इसके अतिरिक्त यह पहल भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता से भी जुड़ी हुई है। ऊर्जा और विदेशी मुद्रा पर अत्यधिक बाहरी निर्भरता किसी भी राष्ट्र को वैश्विक दबावों के प्रति संवेदनशील बना देती है। यदि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, युद्ध, प्रतिबंध या आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं, तो तेल और डॉलर पर निर्भर राष्ट्रों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता और विदेशी मुद्रा संरक्षण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है।

प्रधानमंत्री की यह सोच उसी व्यापक 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टि का हिस्सा है, जिसमें भारत केवल उपभोक्ता राष्ट्र नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर वैश्विक शक्ति बनकर उभरे। यह आ'ान भारतीयों को यह समझाने का प्रयास भी है कि राष्ट्रनिर्माण केवल सरकारों से नहीं होता, नागरिकों की जीवनशैली, उपभोग की आदतें और आर्थिक अनुशासन भी उसमें समान रूप से भागीदार होते हैं। यदि देश का नागरिक अनावश्यक ईंधन की खपत कम करे, स्थानीय उत्पादों को अपनाए, विवेकपूर्ण निवेश करे और भारत के भीतर पर्यटन को बढ़ावा दे, तो यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रहित का सक्रिय योगदान बन जाएगा।

वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश अर्थव्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रशक्ति को सुदृढ़ करने का आ'ान है। यह भारत को भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों, वैश्विक आर्थिक अस्थिरताओं और विदेशी निर्भरता से मुक्त कर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और स्थायी आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में उठाया गया दूरदर्शी कदम है।

क्या भारतीय पीएम मोदी की बात सुनते हैं, लक्षद्वीप के आंकड़े दे रहे हैं गवाही

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील भारतीयों का व्यवहार बदल देती है. लक्षद्वीप पर्यटन के रिकॉर्ड आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जब पीएम मोदी ने राष्ट्रवाद को आर्थिक अपील से जोड़ा, तो मालदीव का बाजार धड़ाम हो गया और लक्षद्वीप का भाग्य बदल गया.

(जीएनएस)।

ईरान युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब भारतीयों से गैरजरूरी विदेशी यात्राओं से बचने, ईंधन बचाने और फिजूलखर्ची कम करने की अपील की है, ऐसे में लक्षद्वीप पर्यटन की कहानी इसका एक हालिया उदाहरण पेश करती है कि लोग उनकी सार्वजनिक अपीलों और संदेशों पर कितनी मजबूती से प्रतिक्रिया देते हैं.

इंडिया टुडे द्वारा आरटीआई (RTI) के तहत हासिल किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या साल 2020 में महज 3,875 थी, जो 2024 में बढ़कर रिकॉर्ड 68,328 पर पहुंच गई. पर्यटकों की संख्या में यह सबसे बड़ा उछाल जनवरी 2024 में पीएम मोदी के द्वीप दौरे के बाद आया, जब उन्होंने वहां के समुद्र तटों और पर्यटन क्षमता को उजागर करने वाली तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए थे.

उनके इस दौरे के बाद तब एक राजनयिक विवाद भी खड़ा हो गया था, जब मालदीव के कुछ मंत्रियों ने इंटरनेट पर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं. इन टिप्पणियों के कारण भारत में भारी आक्रोश फैल गया था, मालदीव के बहिष्कार की मांग उठने लगी थी और एक बड़ा अभियान शुरू हो गया था, जिसमें भारतीयों को विदेशी द्वीपों के

बजाय लक्षद्वीप चुनने के लिए प्रेरित किया गया था. आंकड़े बताते हैं कि कई लोगों ने वास्तव में उस संदेश पर ध्यान दिया और उस पर अमल किया है.

भारतीयों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बना लक्षद्वीप

लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या साल 2023 के 46,551 से बढ़कर 2024 में 68,328 हो गई, जो एक साल के भीतर लगभग 47 प्रतिशत का उछाल है. ठीक इसी समय, मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई. मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मालदीव पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या साल 2023 के 2,09,193 से घटकर 2024 में 1,30,805 रह गई, जो कि 37.5 प्रतिशत की गिरावट है. भारत, जो कभी मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजारों में से एक था, आगंतुकों की हिस्सेदारी के मामले में खिसककर छठे स्थान पर आ गया.

लक्षद्वीप जाने वाले टूरिस्टों की हुई बढ़ोतरी

यह विपरीत रुझान हाल के वर्षों में इस बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण बन गया कि कैसे पीएम मोदी के सार्वजनिक संदेशों ने उपभोक्ताओं के व्यवहार और यात्रा के विकल्पों को प्रभावित किया. मोदी के लक्षद्वीप पोस्ट के बाद मशहूर हस्तियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने इस अभियान को और बढ़ावा दिया. सोशल मीडिया पर विदेश यात्रा करने के बजाय भारतीय गंतव्यों को तलाशने की अपीलों की बाढ़ आ गई. लक्षद्वीप, जो मालदीव जैसी समानताएं होने के बावजूद लंबे समय तक अपेक्षाकृत अविकसित रहा था, अचानक राष्ट्रीय पर्यटन का एक प्रतीक बन गया.

यह मामला अब इसलिए फिर से चर्चा में है, क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में जो अनिश्चितता बनी है, उसके बीच पीएम मोदी ने भारतीयों से अपनी आदतें बदलने को कहा है. पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे बिना वजह विदेश यात्रा न करें, पेट्रोल-डीजल कम खर्च करें, सरकारी बसों-ट्रेनों का इस्तेमाल करें और सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाल दें, ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहे. लक्षद्वीप के उदाहरण से पता चलता है कि जब मोदी देशहित से जुड़ी कोई अपील करते हैं, तो आम जनता की सोच और आदतों में इसका सीधा असर देखने को मिलता है. एक मजेदार बात यह है कि आरटीआई (फ्ळक) के जवाब में सरकार ने 2024 तक के आंकड़े तो विस्तार से दिए हैं, लेकिन साल 2026 में अर्जी दिए जाने के बावजूद 2025 के आंकड़े शेयर नहीं किए हैं. मोदी के दौरे के बाद पर्यटकों की संख्या में जो भारी उछाल आया था, उसे देखते हुए इस नए डेटा का न मिलना काफी हैरान करने वाला है.

सुवेंदु अधिकारी को हराने के लिए टीएमसी ने पानी की तरह बहाए 100 करोड़? लिफाफे में बंटे नोट, दावों से हड़कंप!

पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली नंदीग्राम विधानसभा एक बार फिर भीषण सियासी संग्राम के केंद्र में आ गई है। इस बार विवाद किसी चुनावी रैली या बयानबाजी को लेकर नहीं, बल्कि एक बेहद सनसनीखेज और गंभीर आरोप के बाद खड़ा हुआ है। आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के नंदीग्राम से उम्मीदवार शाहिदुल हक ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के शीर्ष नेतृत्व पर एक ऐसा बम फोड़ा है, जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है।

शाहिदुल हक का सीधा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में धूल चटाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कोई छोटी-मोटी रकम नहीं, बल्कि पूरे 100 करोड़ रुपये का एक खास 'चुनावी बजट' तैयार किया था। उन्होंने इस पूरे खेल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के लिए रणनीति बनाने वाली चुनावी कंसल्टिंग कंपनी आई-पैक (क-PAC) को सीधे कटघरे में खड़ा किया है।

चुनाव प्रचार के दौरान पर्दे के पीछे हुए कथित खेल का पदार्फाश करते हुए एजेयूपी (AJUP) के उम्मीदवार शाहिदुल हक ने बेहद चौंकाने वाली बातें कही हैं। उनका आरोप है कि मतदान से ठीक पहले नंदीग्राम के कोने-कोने में टीएमसी कार्यकर्ताओं और आई-पैक के सदस्यों के जरिए वोटरों को लुभाने के लिए जमकर पैसे बांटे गए थे। शाहिदुल के मुताबिक, नंदीग्राम के हर घर में गुपचुप तरीके से कैश से भरे लिफाफे पहुंचाए गए, जिनमें 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की नकदी भरी हुई थी।

हालांकि शाहिदुल हक ने इस दौरान नंदीग्राम की समझदार जनता की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा,

"नंदीग्राम के आम लोगों ने टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कार और अभिषेक बनर्जी के लोगों से नोटों से भरे वो लिफाफे जरूर ले लिए, लेकिन जब वे वोटिंग बूथ के अंदर गए, तो उन्होंने ईवीएम पर बीजेपी का बटन ही दबाया।"

हक ने आगे कहा कि जनता ने पैसे जेब में रखने के बावजूद राज्य में एक साफ-सुथरी और मजबूत सरकार बनाने के लिए पवित्र कार की जगह सुवेंदु अधिकारी को चुना। वे नंदीग्राम के इन जागरूक और समझदार मतदाताओं को दिल से सलाम करते हैं।

शाहिदुल हक के आरोप सिर्फ पैसे बांटने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने इस पैसे के सोर्स को लेकर देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर और डरावना दावा कर दिया है। पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर की पार्टी के उम्मीदवार हक का कहना है कि चुनाव अभियान में इस्तेमाल की गई यह भारी-भरकम रकम किसी लीगल या वैध रास्ते से नहीं आई थी।

उनके मुताबिक, "नंदीग्राम के चप्पे-चप्पे में जो 100 करोड़ रुपये पानी की तरह बहाए गए, वे असल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और कई अन्य विदेशी मुल्कों से भारत भेजे गए थे। इस बहुत बड़े विदेशी फंड को हवाला या अन्य अवैध रास्तों के जरिए राज्य के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।" हक ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि विदेशों से इस फंड को देश में मंगवाने और इसे जमीन पर बंटवाने के पीछे सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी का हाथ था।

इस पूरे मामले को देश के खिलाफ एक बड़ी वित्तीय साजिश करार देते हुए एजेयूपी नेता शाहिदुल हक ने अब देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों से कड़े एक्शन की मांग की है। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि उनके पास इन गंभीर दावों को सच साबित करने के लिए क्या पुख्ता सबूत या सूत्र हैं, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर टीएमसी को पूरी तरह घेर लिया है।

शाहिदुल हक ने मांग की है कि इस देश विरोधी वित्तीय साजिश के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (एऊ) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (उइक) को तुरंत एक्शन में आना चाहिए। उन्होंने कहा,

"इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए और इस काले धन के असली सोर्स का पता लगाने के लिए एक बड़ी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही इस साजिश के मुख्य सूत्रधार अभिषेक बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए।"

अब देखना यह होगा कि इस विस्फोटक दावे के बाद बंगाल की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है और टीएमसी इस पर क्या पलटवार करती है।

(नोट: ये स्टोरी सोशल मीडिया पर किए गए दावों के आधार पर लिखी गई है, जिसकी पुष्टि नहीं की जा रही है।)

ट्रंप जैसा दिखने वाला भैंसा हुआ वायरल, लोगों ने बताया हूबहू

बांग्लादेश में इस बार ईद-उल-अजहा से पहले दो भैंसे अचानक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं। इन भैंसों के नाम दुनिया के दो बड़े नेताओं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजमिन नेतेनयाहू के नाम पर रखे गए हैं। इन दोनों जानवरों के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इन्हें देखने के लिए दूर-दूर से पहुंच रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नारायणगंज के पाईकपारा इलाके में रहने वाला करीब 700 किलोग्राम वजन का एक सफेद भैंसा सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस भैंसे का नाम डोनाल्ड ट्रंप रखा गया है। स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि इसके सिर के सुनहरे बाल और चेहरे की बनावट काफी हद तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसी दिखती है।

फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस भैंसे के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।वीडियो देखने वाले कई लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि यह ट्रंप का भैंसा वर्जन लगता है। कुछ यूजर्स ने इसके बालों को ट्रंप के मशहूर हेयरस्टाइल से जोड़कर मीम्स भी बनाए हैं।

कैसे पड़ा 'डोनाल्ड ट्रंप' नाम?

भैंसे के मालिक जियाउद्दीन मृधा ने बताया कि उन्होंने इस जानवर को करीब 10 महीने पहले राजशाही के पशु बाजार से खरीदा था। उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई ने मजाक-मजाक में इसके सिर पर भूरे बाल देखकर इसका नाम "डोनाल्ड ट्रंप" रख दिया। उन्होंने बताया कि- "यह स्वभाव से काफी शांत है। आमतौर पर सफेद भैंसे ज्यादा आक्रामक नहीं होते और जब तक उन्हें उकसाया न जाए, वे आराम से रहते हैं।" स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तुलना सिर्फ मजाक नहीं है, बल्कि भैंसे की शक्ल सच में ट्रंप जैसी लगती है। एक महिला ने बताया कि जब उन्होंने फेसबुक पर इसकी तस्वीरें देखीं, तो उन्हें पहली नजर में ही डोनाल्ड ट्रंप की याद आ गई। महिला ने कहा, "इसके चेहरे की बनावट और हेयरस्टाइल काफी हद तक ट्रंप जैसे लगते हैं।"

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह भैंसा ट्रंप से अलग काफी शांत और विनम्र स्वभाव का है।

ऐसे ही एक और भेंसे को देखकर लोगों का कहना है कि उसकी बनावट इजरायली पीएम बेन्जमिन नेतन्याहू जैसी है। हालांकि इस भैंसे पर देखने वालों की राय बंटी हुई दिखी। कुछ बात से सहमत हुए और कुछ असहमत। वीडियो देखकर पहुंचे लोग स्थानीय निवासी रसेल ने बताया कि वह फेसबुक पर वीडियो देखने के बाद खासतौर पर इस भैंसे को देखने आए थे। उन्होंने कहा, "यह सच में ट्रंप जैसा दिखता है। इसका चेहरा और बाल काफी मिलते-जुलते हैं।"

एक अन्य यूजर मिम ने कहा कि पहले उन्हें लगा था कि लोग बढ़ा-चढ़ाकर बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में देखने के बाद उन्हें भी यह तुलना सही लगी। उन्होंने कहा, "यह नाम इस पर पूरी तरह फिट बैठता है।"

खास डाइट से बना इतना विशाल

भैंसे के मालिक के मुताबिक, दक्षिण एशिया में सफेद भैंसे काफी दुर्लभ माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस भैंसे को मक्का, सोयाबीन और चोकर जैसी पौष्टिक चीजें खिलाई गईं, जिसकी वजह से इसका वजन और शरीर इतना मजबूत बना। उन्होंने यह भी बताया कि यह भैंसा पहले ही बिक चुका है।

ईद से पहले बन गए इंटरनेट स्टार

ईद-उल-अजहा से पहले इन दोनों भैंसों की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर इनके वीडियो और तस्वीरें लाखों बार देखी जा चुकी हैं। कई लोग इन्हें सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि "वायरल सेलिब्रिटी भैंसे" कहकर बुला रहे हैं।

चारबाग से वसंतकुंज तक जाना आसान, लखनऊ मेट्रो विस्तार को योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (चारबाग से वसंतकुंज) के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. के मध्य त्रिपक्षीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) के निष्पादन को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस परियोजना की डीपीआर को पहले ही कैबिनेट में अनुमोदित किया जा चुका था और अब 5801.05 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर सहमति दी गई है।

परियोजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत भागीदारी होगी। चारबाग से वसंतकुंज तक बनने वाला यह ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा तथा नागरिकों को आधुनिक और सुगम सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा।

गौरतलब है कि लखनऊ मेट्रो फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की डीपीआर को 5 मार्च 2024 को सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 सितंबर 2025 को परियोजना की कुल लागत 5801.05 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान करते हुए परियोजना का अनुमोदन किया था।

भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में यह शर्त रखी गई थी कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय एमओयू किया जाएगा।

इसी क्रम में न्याय विभाग द्वारा विधिवत परीक्षण एवं संशोधन के बाद तैयार एमओयू के प्रारूप को अब योगी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार परियोजना में राज्य सरकार की भूमिका और दायित्वों को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

लखनऊ में प्रधानों का प्रदर्शन, पंचायत चुनाव समय से कराने की मांग, डिप्टी सीएम ने मिठाई खिलाकर पानी पिलाया

(जीएनएस)।

लखनऊ : अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन, उत्तर प्रदेश के बैनर तले पंचायत प्रतिनिधियों ने सोमवार को जीपीओ पार्क में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. 'लोकतंत्र बचाओ, पंचायत बचाओ' के नारे के साथ प्रदेशभर से पहुंचे ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई.

प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मिठाई खिलाकर पानी पिलाया. उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी लिया. उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगी.

डिप्टी सीएम ने सुनी समस्या.

अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. भारतीय संविधान के भाग-9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243-ए और 243-ङ पंचायत चुनावों को समयबद्ध तरीके से कराने की संवैधानिक गारंटी देता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार समय से चुनाव नहीं कराती और पंचायतों पर प्रशासक नियुक्त करती है, तो यह लोकतंत्र और ग्राम स्वराज की अवधारणा के खिलाफ होगा.

उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाकर नौकरशाही के माध्यम से पंचायतों का संचालन करना ग्रामीण जनता के मताधिकार का सीधा हनन है. संगठन की मांग है कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं और किसी भी स्थिति में पंचायतों पर बाहरी प्रशासक न बैठाए जाएं. संगठन ने यह भी मांग उठाई कि यदि किसी कारणवश चुनाव में देरी होती है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर निर्वाचित ग्राम प्रधानों को ही प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देते हुए कार्यवाहक प्रशासक घोषित किया जाए.

प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान और पंचायतों के अधिकारों की रक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की पहली इकाई हैं और उन्हें कमजोर करना संविधान की आत्मा पर प्रहार होगा. धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'पंचायतों पर प्रशासक नहीं चलेगा', 'लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे' और 'ग्राम स्वराज हमारा अधिकार' जैसे नारे लगाए. संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.

लखनऊ पीजीआई अस्पताल में कैंसर मरीज ने की आत्महत्या, इलाज के खर्च और बीमारी से था परेशान

राजधानी लखनऊ स्थित संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (पीजीआई) से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक कैंसर पीड़ित ने इलाज के बढ़ते खर्च और आर्थिक तंगी से परेशान होकर ब्लेड से अपना गला काट कर खुदखुशी कर ली हैं.

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पीजीआई अस्पताल से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है जहां एक कैंसर पीड़ित ने ब्लेड से अपना गला काट कर खुदखुशी कर ली हैं हालांकि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी हैं और मामले की जांच में जुट गई हैं.

वॉर्ड के भीतर ब्लेड से काटा गला, मानसिक रूप से था परेशान

राजधानी लखनऊ स्थित संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (पीजीआई) अस्पताल में भर्ती एक कैंसर मरीज ने कथित तौर पर ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि मरीज लंबे समय से लीवर कैंसर से पीड़ित था और इलाज के बढ़ते खर्च व बीमारी के दर्द के कारण वह मानसिक तनाव में भी चल रहा था. बताया जा रहा है कि मरीज ने अस्पताल के वॉर्ड के भीतर ही ब्लेड से अपना गला काट लिया. जब तक डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को घटना की जानकारी हुई, तब तक अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी.

एक महीने से चल रहा था इलाज

जानकारी के मुताबिक मृतक मरीज पिछले करीब एक महीने से पीजीआई अस्पताल में भर्ती था, जहां उसका लीवर कैंसर का इलाज चल रहा था. वहीं परिजनों और अस्पताल सूत्रों के अनुसार, मरीज बीमारी की गंभीरता और लगातार बढ़ रहे इलाज के खर्च को लेकर काफी परेशान था और आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था.

अस्पताल में मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

वहीं इस घटना से मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्यकर्मियों में हड़कंप मच गया और घटना के बाद अस्पताल प्रशासन भी सकते में आ गया. हालांकि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और दक्षिण जोन के पुलिस उपायुक्त अमित कुमार आनंद ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. वहीं पुलिस ने मौके से वह ब्लेड भी बरामद कर लिया है, जिससे मरीज ने कथित तौर पर आत्महत्या की. साथ ही डीसीपी साउथ अमित कुमार आनंद ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

'आदेश था 72 का और गिरा दिए 240 चैंबर...', लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज और बुलडोजर एक्शन की पूरी कहानी

लखनऊ में पुराने हाईकोर्ट परिसर के पास वकीलों के चैंबरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा हुआ. वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने 72 चैंबर हटाने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने करीब 240 चैंबर गिरा दिए. विरोध करने पर वकीलों से बदसलूकी भी की गई.

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को वकीलों के अवैध चैंबरों पर चला बुलडोजर बड़ा विवाद बन गया है. प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और विरोध कर रहे वकीलों पर लाठीचार्ज भी किया गया. इस घटना के बाद बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली है. वकीलों ने इसे 'लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन' बताते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. ऐसे में आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी...

दरअसल हाईकोर्ट ने कुछ अवैध चैंबरों को हटाने का निर्देश दिया था. वकीलों के चैंबर शामिल ही नहीं थे, बावजूद इसके उन्हें भी तोड़ दिया गया. वकीलों का कहना है कि वे पिछले करीब 30 वर्षों से वहीं बैठकर वकालत कर रहे हैं और अचानक इस तरह की कार्रवाई उनके रोजगार पर सीधा हमला है.

जिसके बाद नगर निगम की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और चैंबर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई. हालांकि इस दौरान वकीलों ने विरोध भी किया. जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया. वकीलों का आरोप है कि हाईकोर्ट ने केवल 72 चैंबर हटाने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने आदेश की आड़ में करीब 240 चैंबरों पर कार्रवाई कर दी. उनका कहना है कि जिन चैंबरों को चिन्हित किया गया था, उनमें कई वकीलों की तबीयत भी बिगड़ गई. कुछ अधिवक्ता जमीन पर बैठकर विरोध जताते रहे तो कुछ ने कार्रवाई रोकने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बहस की. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया.

जहां 30 सालों से बैठ कर रहे थे काम, उसे ही तोड़ दिया गया

अधिवक्ताओं ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें वहां से हटाया जा रहा है तो पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी. वहीं प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं रोकी और उचित समाधान नहीं निकाला तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. वहीं प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

विवाद पर डीसीपी का आया बयान

मामले में डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित का भी बयान आया है. उनका कहना है कि सभी को नोटिस दिया जा चुका है. कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है. विरोध ऐसे कामों में होता है. हम तैयार है ऐसे कार्रवाई के लिए. कानून सब के लिए बराबर है.

राजीव चौक जैसा इंटरचेंज बनेगा चारबाग, अमीनाबाद से वसंतकुंज तक 12 स्टेशनों वाला नया रूट, लखनऊ मेट्रो के विस्तार पर बिग अपडेट

वेस्ट कॉरिडोर पर आज सुबह यूपी कैबिनेट की मुहर लग गई है. इससे पुराने लखनऊ और नए लखनऊ के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बनेगी और शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा. जानिए कहां-कहां से गुजरेगी ये मेट्रो?

(जीएनएस)।

लखनऊ, यूपी की योगी सरकार ने लखनऊ में मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी दे दी है. सरकार ने राजधानी के सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ी कदम उठाया है. योगी कैबिनेट की मीटिंग में लखनऊ मेट्रो के फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर समेत 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

कनेक्टिविटी-ट्रैफिक के हिसाब से गेमचेंजर

इस परियोजना के तहत चारबाग से बसंतकुंज तक मेट्रो सेवा शुरू होगी. ये पुराने लखनऊ के इलाकों में कनेक्टिविटी और ट्रैफिक के हिसाब से गेमचेंजर साबित होने वाली है. इसकी लंबाई करीब 11.16 किलोमीटर होगी, जिसमें स्टेशनों की संख्या 12 होगी, जिसमें 7 अंडरग्राउंड और 5 एलिवेटेड होंगे.

नया और पुराना लखनऊ होगा कनेक्ट

ये परियोजना पुराने और नए लखनऊ के बीच मेट्रो लिंक का काम करने वाली है और पुराने लखनऊ के ट्रैफिक जाम के जंजाल से राहत मिलेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो पुराने लखनऊ की घनी आबादी को ध्यान में रखते हुए इसका 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा अंडरग्राउंड मेट्रो होगा.

कहां-कहां बनेंगे स्टेशन?

चारबाग स्टेशन से मेट्रो पुराने लखनऊ के बाजारों से होकर वसंत कुंज पहुंचेगी. इसके स्टेशन चारबाग, गौतम बुद्ध मार्ग (बांसमंडी), अमीनाबाद, पांडेयगंज, लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन, केजीएमयू मेडिकल कॉलेज चौराहा से नवाजुद्दीन हैदर रोड, ठाकुर गंज, बाला गंज, सरफराजगंज, मूसाबाग से वसंतकुज होंगे, जिसमें हैदर रोड तक के पहले सात मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे. यह चारबाग रेलवे स्टेशन को सीधे हरदोई रोड पर वसंत कुंज से कनेक्ट करेगा.

मेट्रो से किसे होगा फायदा?

अमीनाबाद, चौक, मेडिकल कॉलेज और ठाकुरगंज लखनऊ के वो इलाके हैं, जहां सड़कों पर लोगों को भारी ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ती है. मेट्रो शुरू होने से यहां ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा. ये मेट्रो रूट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), बलरामपुर अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर को सीधे कनेक्ट करेगा, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को फायदा होगा.

नए ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का इंटरचेंज हब

अभी चारबाग स्टेशन लखनऊ के नॉर्थ-साउथ मेट्रो कॉरिडोर (मुंशीपुलिया से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट) और इस नए ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का इंटरचेंज हब बनेगा. बिन स्टेशन से बाहर निकले ही यात्री सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलकर दूसरी लाइन की मेट्रो पकड़ पाएंगे. इस मेट्रो रूट की संशोधित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (उढफ) लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (छटफ्ह/वढटफ्ह) ने तैयार की थी. पहले यह रूट थोड़ा अलग था.

यूपी कैबिनेट की मंजूरी

उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट की फाइल केंद्र सरकार (शहरी आवास विकास मंत्रालय) से हरी झंडी मिलेगी. फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (PIB) से भी मंजूर मिलेगी. विदेशी फंडिंग एजेंसी जैसे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से वित्तीय निवेश पर चर्चा हो रही है. ताकि सिविल कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से हो पाएं.

जानें मेट्रो विस्तार का प्लान

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम (वढटफ्ह) के टऊ सुशील कुमार का कहना है कि लखनऊ मेट्रो का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के प्री सिविल कंस्ट्रक्शन कार्यों में तेजी से लाई गई है. बिजली के खंबे, तार और अन्य अड़चनों को दूर किया जा रहा. ये लखनऊ के ट्रैफिक मैनेजमेंट को और बेहतर बनाएगा. अब अगर लखनऊ मेट्रो के विस्तार के प्लान की बात करें तो 2047 तक लखनऊ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा. जिसमें इंदिरानगर से अनौराकला तक 9.27 किमी, अनौराकला से बाराबंकी तक 14 किमी, राजाजीपुरम से आईआईएम तक 18.42 किमी, मुंशीपुलिया से जानकीपुरम तक 6.29 किमी, इंदिरानगर से सीजी सिटी तक 7.7 किमी, चारबाग से कल्ली पश्चिम तक 13 किमी, सीजी सिटी से एयरपोर्ट तक 19.08 किमी और कल्ली पश्चिम से मोहनलालगंज तक 6 किमी विस्तार होगा.

शहर में आर्बिटल नेटवर्क

लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी जैसे 6 जिलों को मिलाकर योगी सरकार आर्बिटल रेल नेटवर्क भी बना रही है. ये रिंग रोड की तरह लखनऊ के आसपास के जिलों को जोड़ने वाले लोकल रेल नेटवर्क होगा. ये 170 किलोमीटर लंबा आर्बिटल रेल कॉरिडोर होगा. केंद्र सरकार ने 7500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. जिसमें पिपरसंड, अमौसी, आलमनगर, ट्रांसपोर्टनगर, उतरेटिया, मोहनलालगंज, अनूपगंज, मलिहाबाद, इटौंजा सहित कई रेलवे स्टेशनों को कनेक्ट करेगा. ये प्रोजेक्ट 2031 में पूरा होगा. गोमतीनगर, बादशाहनगर, डालीगंज, ऐशबाग के साथ मानकनगर, दिलकुशा, उतरेटिया के बीच भी ऐसी सर्कुलर रेल चलाने का भी रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है.

कौन हैं क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया? पीएम मोदी को दिया खास तोहफा, चर्चा में क्यों आई?

(जीएनएस)।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गई। इस दौरान स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस Victoria, Crown Princess of Sweden ने एक भव्य समारोह में पीएम मोदी को स्वीडन का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार (कमांडर ग्रैंड क्रॉस)' से नवाजा। इस सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी यह अवॉर्ड पाने वाले पहले एशियाई नेता बन गए हैं। इसे भारत और स्वीडन के रिश्तों के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।

क्या है 'रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार'?

Royal Order of the Polar Star स्वीडन के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित राज्य सम्मानों में से एक है। इसकी शुरूआत साल 1818 में हुई थी। करीब दो सदियों पुराना यह सम्मान उन विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों और बड़े नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने स्वीडन के साथ मजबूत रिश्ते बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष योगदान देने का काम किया हो। स्वीडन में इस अवॉर्ड को बेहद सम्मानजनक माना जाता है और इसे पाने वाले नेताओं की संख्या भी काफी सीमित रही है।

कौन हैं क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया?

Victoria, Crown Princess of Swede»»f स्वीडन के राजा Carl XVI Gustaf की सबसे बड़ी बेटी हैं और फिलहाल स्वीडिश सिंहासन की आधिकारिक उत्तराधिकारी हैं। 48 साल की विक्टोरिया धीरे-धीरे भविष्य की राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। अगर वह भविष्य में सिंहासन संभालती हैं, तो वह स्वीडन के इतिहास की केवल चौथी शासक रानी बनेंगी। यही वजह है कि यूरोप की राजनीति और राजघरानों में उनकी काफी अहमियत मानी जाती है।

जन्म के बाद भी क्यों छिन गई थी उत्तराधिकारी की जगह?

दिलचस्प बात यह है कि 1977 में जन्म लेने के बावजूद विक्टोरिया शुरूआत में सिंहासन की उत्तराधिकारी नहीं थीं। दरअसल, 1979 में उनके छोटे भाई Prince Carl Philip का जन्म हुआ। उस समय स्वीडन में पुराने नियम लागू थे, जिनमें केवल पुरुष संतान को प्राथमिकता दी जाती थी। इसी वजह से विक्टोरिया को उत्तराधिकार की लाइन से हटा दिया गया था और उनके भाई को आगे कर दिया गया।

1980 में बदला संविधान और बदल गई किस्मत

साल 1980 में स्वीडन ने अपने संविधान में बड़ा बदलाव किया। देश ने एब्सोल्यूट प्रिमोजेनर यानी अब राजा की सबसे बड़ी संतान ही उत्तराधिकारी होगी, चाहे वह बेटा हो या बेटी। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद विक्टोरिया को आधिकारिक तौर पर क्राउन प्रिंसेस घोषित किया गया और उन्हें भविष्य की रानी का दर्जा मिला। यह फैसला यूरोप में महिला अधिकारों और राजशाही सुधारों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया।

क्यों कहा जाता है 'गॉडमदर ऑफ यूरोप'?

अपनी शाही जिम्मेदारियों के अलावा विक्टोरिया एक बेहद खास निक नेम 'गॉडमदर ऑफ यूरोप' से भी जानी जाती हैं। यूरोप के शाही परिवारों में वह सबसे लोकप्रिय गॉडपेरेंट्स में से एक मानी जाती हैं। यूरोप की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार, गॉडपेरेंट बच्चों के आध्यात्मिक संरक्षक और मार्गदर्शक माने जाते हैं। विक्टोरिया के यूरोप के लगभग हर बड़े शाही परिवार में गॉडचाइल्ड मौजूद हैं।

तीन भावी राजा-रानियों की भी हैं गॉडमदर

सबसे खास बात यह है कि विक्टोरिया के गॉडचाइल्ड्स में यूरोप के तीन भावी राजा और रानियां भी शामिल हैं। यही वजह है कि उन्हें केवल स्वीडन की भावी रानी नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के शाही परिवारों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण हस्ती माना जाता है। उनकी यह भूमिका उन्हें मॉडर्न यरोपियन एरिस्टोक्रेसी के बीच एक मजबूत और एकजुट करने वाले चेहरे के रूप में स्थापित करती है।

19 मई को घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये गाइडलाइन!

बंद रहेंगे कई रास्ते, नई एडवाइजरी

देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की हलचल शुरू होने वाली है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 28 मई से 1 जून 2026 तक 'ट्विन समिट' का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट और इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम शामिल हैं। इस महा-आयोजन को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह कमर कस चुकी है।

इसी सिलसिले में कल यानी 19 मई 2026 (मंगलवार) को दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लुटियंस दिल्ली और भारत मंडपम के आसपास के इलाकों में एक मेगा 'समिट रिहर्सल' की जाएगी। इस दौरान नई दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा और कुछ मार्ग पूरी तरह बंद भी किए जा सकते हैं। अगर आप कल इस दौरान घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ये गाइडलाइन जरूर नोट कर लें।

बिना फंसे कैसे करें दिल्ली में सफर? इन रास्तों का करें इस्तेमाल

रिहर्सल के दौरान आम जनता को ज्यादा परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक रास्तों का सुझाव दिया है, जो बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगे:

रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग: दिल्ली के ये दोनों मुख्य रास्ते दोनों दिशाओं में पूरी तरह खुले रहेंगे, आप इनका इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं।

उत्तर से दक्षिण : अगर आप नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो राजघाट और सराय काले खां होते हुए रिंग रोड का रूट पकड़ें।

पश्चिम से दक्षिण : वेस्ट दिल्ली से साउथ जाने वाले लोग धौला कुआं, मोती बाग और भीकाजी कामा प्लेस वाले रिंग रोड रूट का इस्तेमाल करें।

पूर्व से दक्षिण : ईस्ट दिल्ली से साउथ जाने के लिए सराय काले खां और बारापुला या आश्रम चौक कॉरिडोर वाला रास्ता सबसे बेस्ट रहेगा।

एयरपोर्ट जाने वाले यात्री: आईजीआई एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए धौला कुआं की तरफ से एनएच-8 और गुरुग्राम रोड पूरी तरह चालू रहेगा।

▶ नई दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स और बंद रहने वाले रास्ते

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दोपहर 12 से 3 बजे के बीच नई दिल्ली के कुछ खास एंट्री पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग होगी और कई रास्ते प्रभावित रहेंगे।

एसपी मार्ग और मथुरा रोड इस रिहर्सल से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और सुरक्षा कारणों से इन्हें कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है। नई दिल्ली में प्रवेश के लिए केवल रिंग रोड और वंदे मातरम